

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

र्सं∘ 36] No. 36] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 1998/माघ 30, 1919 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 1998/MAGHA 30, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

जाँच शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

विषय :- चीन जनवादी गणराण्य से क्लोरोक्वीन फासफेट के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं 16/1/97- ऐ डी डी. -- मैसर्स टाटा फार्मा लि. तथा आई पी सी ए लि. ने सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (डम्प की गई वस्तुओं की पहचान तथा पाटमरोधी शुल्क का निर्धारण तथा वसूली एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा जाएगा) के पास संयुक्त याचिका दायर की है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य से क्लोरोक्वीन फासफेट के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

- स्थिति:—भारत में क्लोरोक्कीन फासफेट के कई उत्पादक है, जिनमें से दो ने संयुक्त रूप से वर्तमान याचिका दायर की है।
 याचिकाकर्त्ता भारत में कुल घरेलू उत्पादन के एक बड़े भाग का उत्पादन करते हैं, और इसीलिए ये घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की शर्तों को पूरा करते हैं।
- 2. संबंधित उत्पाद: —मौजूदा जांच में संबंधित उत्पाद क्लोरोक्वीन फासफेट है। क्लोरोक्वीन फासफेट एक औषधीय उत्पाद है और इसका प्रयोग मलेरिया रोधी नुस्खों को तैयार करने में किया जाता है। क्लोरोक्वीन फासफेट की सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क शीर्ष मं. —के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और मौजूदा जांच के लिए किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।
- संबंधित देश: याचिकाकर्ताओं ने चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों द्वारा पाटन का आरोप लगाया गया है।
- 4. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की विशेषताएं चीन जनवादी गणराज्य से आयात की जा रही वस्तुओं से मिलती जुलती हैं और इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है। अतः बरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित

क्लोरोक्वीन फासफेट को चीन से आयातित क्लोरोक्वीन फासफेट के समान वस्तु के रूप में माना जा सकता है।

इम्पिंग तथा इम्पिंग मार्जिन:—

- (क) सामान्य मूल्य: —याधिकाकर्ता ने मुख्य -मुख्य कच्ची सामग्रियों (बिना शुल्क के) के आयात मूल्यों तथा उनके पास उपलब्ध अन्य सूचना के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य में क्लोरोक्वीन फासफेट की उत्पादन की लागत का निर्धारण किया है फ्रांस में क्लोरोक्वीन फासफेट के सामान्य मूल्य के संबंध में प्रथम दृष्ट्या प्रयोप्त साक्ष्य हैं।
- (ख) निर्यात मूल्य: याचिकाकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के लिए निम्नलिखित निर्यात भूल्यों का दावा किया है:

वर्ष	मात्रा (कि.ग्राम)	भूल्य (लाख रु. में)	दर (रु. प्रति कि.ग्राम)
1 99 4 <i>-</i> 95	34623	308.99	892
1 99 5-96	176488	1301.38	732
1996-97	. 81213	623.98	768

डीजीसीआईएस के अनुसार 1996-97 (फरवरी, 97 तक) के लिए औसत मूल्य 772 रु. प्रति किया. है जो कि सीआईएफ निर्यात मूल्य है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने एफओबी निर्यात मूल्य का आंकलन किया है। याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़े, चीन जनवादी गणराण्यों में अतर्देशीय भाड़े, उपर्युक्त निर्यात मूल्य में मूल्य समायोजनों का दावा किया है। फ्रांस में कलोरोक्वीन फासफेट के निर्यात मूल्य से संबंधित प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं।

इस बात के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य हैं कि चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी ज्यादा है जिस कीमत पर भारत में इसका निर्यात किया गया है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों द्वारा संबंधित वस्तुओं का पाटन किथा जा रहा है।

- 6. श्रिति:—घरेलू उद्योग से संबंधित विधिन्न आर्थिक संकेतक जैसे उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा लाभ/हानि इत्यादि सामूहिक और संचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या यह इंगित करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस बात के प्रथम-दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- 7. **पाटनरोधी जांच की शुरूआत:** —अत: प्राधिकारी उक्त देश के मूल के या वहां से निर्यातित संबंधित वस्तु के आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।
- 9. सूचना का प्रस्तुतीकरण: संबद्ध माने जाने वाले चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों और भारत के आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित विधि से सुसंगत सूचना तथा अपने विचार निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय, पाटन-रोधी प्रभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत करे। कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित विधि पूर्वक जांच से संबंधित अपनी सूचना भेज सकती है।
- 10. समय-सीमा: —वर्तभान जाँच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए तिक यह प्राधिकारी के उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से चालीस दिनों के भीतर पहुँच जाए। परन्तु ज्ञात निर्यातकों और आयातकों जिन्हें अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं, को उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तिथि से चालीस दिनों के भीतर यह सूचना भेजी जानी आवश्यक है।
- 11. सार्वजिनिक मिसिल का निरीक्षण: नियम 6(7) की शर्तों के अनुसार कोई भी इच्छुक पार्टी सार्वजिनिक मिसिल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतरण होते हैं।
- 12. यदि कोई पार्टी पहुँचने से मना करती है अथवा अन्यथा वह उपयुक्त अविध में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करती है अथवा सूचना में सांकेतिक रूप से अङ्चन डालती है, तो ऐसी स्थित में प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है।

MINISTRY OF COMMERCE INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 1998

Subject: - Initiation of anti-dumping investigation concerning import of Chloroquine Phosphate from China PR.

No. 16/1/97-ADD.—M/s: Tata Pharma Ltd. and IPCA Ltd. have filed a joint petition in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Choloroquine Phosphate from the People's Republic of China (referred to as China PR hereinafter) and requested for anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

- Standing:- There are a number of producers of Chloroquine phosphate in India, two of whom have jointly filed the present petition. The petitioners account for a major proportion of the total domestic production in India and, therefore, satisfy the standing to file the present application on behalf of the domestic industry.
- 2. Product involved: The product involved in the present investigation is Chloroquine phosphate. Chloroquine phosphate is a pharmaceutical product and is used in anti-malarial formulations. Chloroquine phosphate is classified under custom sub-heading no. 2939.21 of the Customs Tariff Act. The classification is, however, indicative only and in no way binding on scope of the present investigations.
- Country(les) involved: The petitioners have alleged dumping by the exporters from China PR.
- 4. <u>Like Goods</u>: The petitioners have alleged that goods produced by them have characteristics similar to the goods being imported from China PR and the two are being consumed interchangeably. Chloroquine phosphate produced by the domestic industry has, therefore, been treated as like article to the Chloroquine phosphate imported from China PR.
- 5. **Dumping and Dumping Margin:**
- a) Normal Value: The petitioners have constructed cost of production of Chloroquine phosphate in China PR, based on the import prices of major raw materials and other information available with it. There is sufficient prime facile evidence with regard to normal value of Chloroquine phosphate in China PR.
- b) <u>Export Price</u>: The petitioner has claimed the following export prices for the past three years:

Year	<u>Volume</u> (kgs.)	<u>Value</u> (Rs. lacs)	Rate Rs. per kg.	
1994-95	34623	308.99	892	
1995-96	176488	1301,38	732	
1996-97	81213	623.96	768	

As per DGCIS, the average price for 1996-97 (upto Feb., 97) is Rs. 772 per kg. The petitioners have claimed price adjustments in the on account of ocean freight, inland freight in China PR, insurance, and packing expenses. There is sufficient prime facile evidence with regard to export price of Chloroquine phosphate in China PR.

There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the product under consideration in China PR is significantly higher than the price at which it has been exported to India, indicating, prime facie, that the subject goods are being dumped by the exporters from China PR.

- 6. <u>Injury</u>: The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, market share, profit/loss etc. also collectively and cumulatively, prima facie, indicate that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient prime facie evidence that the imports of the product under consideration have caused injury to the domestic industry.
- 7. <u>Initiation of Anti-Dumping Investigation</u>: The Authority, therefore, initiates antidumping linvestigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the said country.
- 8. **Period of Investigation**: The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April, 1996 to 30th June, 1997.
- 9. <u>Submission of Information</u>: The exporters in China PR and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Anti Dumping Division, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
- Time Limit: Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.
- 11. <u>Inspection of Public File</u>: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
- 12. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority